

“विदेश मंत्रालय में इंडो-पैसिफिक विंग ने भारत की ‘पूर्व की ओर देखो’ नीति को रणनीतिक सहयोग प्रदान किया है।”

यद्यपि इंडो-पैसिफिक शब्द पिछले कुछ समय से भारतीय नीति के दायरे में तनावग्रस्त है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून, 2018 में शांगरी-ला संवाद में भारतीय दृष्टि को प्रस्तुत करने के बाद इसने स्पष्टता हासिल की है। इसने रेखांकित किया है कि भारत के लिए इंडो-पैसिफिक का भूगोल अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर ओशिनिया (अफ्रीका के तट से लेकर अमेरिका तक) तक फैला हुआ है, जो प्रशांत द्वीप के देशों में भी शामिल है।

कई तंत्र

भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ राष्ट्रीय इंडो-पैसिफिक दृष्टि का आधार है और आसियान की केंद्रीयता भारतीय कथा में अंतर्निहित है। भारत हिन्द महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ (IORA), आसियान के नेतृत्व वाले पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस, आसियान क्षेत्रीय मंच के साथ-साथ बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्स्टेक) और मेकांग-गंगा आर्थिक गलियारा जैसे तंत्र में सक्रिय भागीदार रहा है। भारत हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी भी आयोजित करता रहा है, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) की नौसेनाएँ भाग लेती हैं।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ अपनी भागीदारी को बढ़ाया है और कोरिया गणराज्य के साथ अपने सहयोग को मजबूत बनाया है। फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के जरिए भारत पैसिफिक आइलैंड देशों के साथ अपनी बातचीत बढ़ा रहा है। अफ्रीका के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी को भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन जैसे तंत्र के आयोजन के माध्यम से देखा जा सकता है। चीन के साथ भारत की बहुस्तरीय समझौते के साथ-साथ रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी एक स्थिर, खुली, सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध भारत-प्रशांत सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

भारत इंडो-पैसिफिक को एक भौगोलिक और रणनीतिक विस्तार के रूप में देखता है, जिसमें 10 आसियान देश दो महान महासागरों को जोड़ते हैं। इसलिए, विशिष्टता, खुलापन, आसियान केंद्रीयता और एकता, इंडो-पैसिफिक की भारतीय धारणा के केंद्र में स्थित है। इस क्षेत्र में सुरक्षा को बातचीत के माध्यम से बनाए रखा जाना चाहिए, एक सामान्य नियम-आधारित आदेश, नेविगेशन की स्वतंत्रता, बिना लाइसेंस के वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादों का निपटारा करने पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, परामर्श, सुशासन, पारदर्शिता, व्यवहार्यता और स्थिरता के संबंध में अधिक कनेक्टिविटी पहल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

एक स्वाभाविक परिणाम

अप्रैल, 2019 में विदेश मंत्रालय (MEA) में इंडो-पैसिफिक विंग की स्थापना एक स्वाभाविक परिणाम को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गयी थी। यह देखते हुए कि इंडो-पैसिफिक शब्द की किस तरह से महत्ता बढ़ रही है। कर रहा है और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख क्षेत्रीय अभिनेता अपने क्षेत्रीय विचारों को कैसे व्यक्त कर रहे हैं, जहाँ उनकी आधिकारिक नीति के बयानों में यह शब्द शामिल है, यह भारत के लिए अपनी इंडो-पैसिफिक नीति को संचालित करने के लिए अनिवार्य हो गया था।

दिसंबर, 2018 में अमेरिकी प्रशांत कमांड का नाम बदलकर अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड और एशिया रिइश्योरेंस इनिशिएटिव

एक्ट का नामकरण इंडो-पैसिफिक के साथ वाशिंगटन के अधिक गंभीर जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। 2016 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा खुली और ओपन इंडो-पैसिफिक अवधारणा का अनावरण किया गया था और ऑस्ट्रेलिया ने 2017 में अपनी विदेश नीति श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की इंडो-पैसिफिक दृष्टि सुरक्षा, खुलेपन और समृद्धि के आस पास केंद्रित थी।

इंडो-पैसिफिक कवर की भारतीय परिभाषा के विशाल भूगोल को देखते हुए, एक ऐसे विभाजन को बनाने के लिए नौकरशाही की पुनर्संरचना की आवश्यकता थी जो विदेश मंत्रालय में विभिन्न क्षेत्रीय प्रभागों की तह में तबदील हो सके और उन देशों की नीतियों की देखभाल कर सके, इंडो-पैसिफिक का हिस्सा हैं। यह विंग प्रधानमंत्री के इंडो-पैसिफिक विजन के लिए एक रणनीतिक सामंजस्य प्रदान करती है, जो आईओआरए (IORA), आसियान क्षेत्र और क्वाड से इंडो-पैसिफिक गतिशीलता को एकीकृत करता है।

आईओआरए के एकीकरण का मतलब है कि ध्यान हिंद महासागर क्षेत्र (IORA) पर केंद्रित रहेगा। यह हिंद महासागर में बढ़ते चीनी कदम और क्षेत्र में चीनी कूटनीति का परिणाम हो सकता है। रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना भी इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे रहे हैं और यह विंग इन दोनों अंगों के साथ समन्वय में भी काम कर सकती है। अपने आस-पास के इलाके में नई दिल्ली के दांव को देखते हुए, अधिक केंद्रित और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक दृष्टि की आधारशिला का निर्माण करता है। जैसा कि आसियान अब अपनी खुद की इंडो-पैसिफिक नीति को आगे बढ़ाने के लिए विचार-विमर्श में शामिल हो चुका है, यह इंडो-पैसिफिक अवधारणा के प्रति उप-क्षेत्रीय संगठन के संदर्भ में एक बदलाव को रेखांकित करता है। प्रारंभ में समूह के भीतर एक भयावह डर था कि इंडो-पैसिफिक अवधारणा सिर्फ आसियान की केंद्रीयता और महत्व पर ध्यान देगी। आसियान क्षेत्र को व्यापक इंडो-पैसिफिक के एक भाग के रूप में देखने से क्षेत्र की सोच में एक विकास दिखाई देता है, जिससे समूह के साथ भारत के जुड़ाव की नई संभावनाएं खुल रही हैं।

आगे की चुनौतियां

भारत की नौकरशाही पारी अपनी क्षेत्रीय नीति को और अधिक सुसंगत रूप से एवं नए सिरे से उद्देश्य की अभिव्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। भारत के समक्ष अभी भी कई चुनौतियां हैं, खासकर यह कि यह चतुर्भुज (क्वाड) पहल को कैसे एकीकृत करेगा, जो 2017 में अपने बड़े भारत-प्रशांत दृष्टिकोण के साथ पुनर्जीवित हो गया है। नए विदेश मंत्रालय डिवीजन के लिए सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों से आगे बढ़ना तथा क्षेत्र के लिए एक अधिक व्यापक नीति को स्पष्ट करना भी महत्वपूर्ण होगा। यदि भारत को अपने क्षेत्रीय जुड़ाव के लिए नए उद्घाटन का लाभ उठाना है, तो विशेष रूप से वाणिज्य और कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देनी होगी।

जबकि भारत लगातार इंडो-पैसिफिक ढांचे में ष्ममावेशिता पर जोर दे रहा है, इसलिए सभी हितधारकों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। इंडो-पैसिफिक के लिए भारत की दृष्टि और अमेरिका की रणनीति के बीच अंतर है तथा चीन एवं रूस जैसे देश भी भारत-प्रशांत को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जैसे ही चीन और अमेरिका के बीच भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है, यदि भारत के दीर्घकालिक राजनीतिक और आर्थिक हितों को संरक्षित रखा जाना है, तो विदेश मंत्रालय के नए प्रभाग को अपना काम पूरा करना होगा। वास्तव में एक नौकरशाही परिवर्तन की आवश्यकता थी, लेकिन बढ़ती चुनौती के परिप्रेक्ष्य में यह देखना आवश्यक होगा कि यह परिवर्तन भारत-प्रशांत में भारत के बढ़ते राजनयिक पदचिह्न को प्रबंधित करने में कितना प्रभावी साबित होगा।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी

क्या है?

- भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मौजूद देशों की भी सहभागिता को बढ़ावा देने के मकसद से लाई गई थी।
- इस नीति ने पूर्व सरकारों की ओर से लुक ईस्ट की नीति को एक कदम आगे बढ़ाया था।
- इस नीति को जब शुरू किया गया, तो इसे एक आर्थिक पहल के तौर पर देखा गया था लेकिन अब इस नीति ने एक राजनीतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक अहमियत भी हासिल कर ली है, जिसके तहत देशों के बीच बातचीत और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक तंत्र की शुरुआत भी कर दी गई है।
- भारत ने इस नीति के तहत इंडोनेशिया, विएतनाम, मलेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और आसियान देशों के साथ ही एशियाई-प्रशांत क्षेत्र में मौजूद देशों के साथ संपर्क को बढ़ाया है।

उद्देश्य

- एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने भारत-आसियान देशों के बीच मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनुफैक्चरिंग, व्यापार, स्किल डेवलपमेंट, शहरी विकास और स्मार्ट सिटी के साथ मेक इन इंडिया जैसी पहल पर जोर दिया है।
- इसके साथ ही साथ देशों के साथ कई तरह के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, अंतरिक्ष और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाना भी इसका मकसद है ताकि क्षेत्र में विकास हो सके और लोग समृद्ध रहें। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाना और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना है।
- विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक इस पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट एक प्राथमिकता है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया।

लुक ईस्ट नीति

- साल 1991 में जब केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी तो लुक ईस्ट पॉलिसी को शुरू किया गया। इस नीति को भारत के विदेश नीति के संदर्भ में एक नई दिशा और नए अवसरों के रूप में देखा गया।
- नरसिम्हा राव के बाद वाजेपई सरकार और फिर यूपीए सरकार ने भी इसे आगे बढ़ाया। इस नीति का मकसद दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन के महत्व को कम करना है।

- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी भारत की 'लुक ईस्ट' पॉलिसी की सराहना की थी। उनके प्रशासन में विदेश मंत्री रहीं हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि उनका देश भारत की इस नीति का समर्थन करना चाहता है।
- हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका ने हिंद और प्रशांत महासागर में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के मकसद से यह बात कही थी।

इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA)

- IORA की स्थापना का उद्देश्य हिन्द महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग तथा सतत् विकास को मजबूत करना है, IORA 21 सदस्य देश तथा 7 वार्ता साझेदार हैं।
- द्वितीय IORA नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक में 9 सदस्य के मंत्री तथा 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
- IORA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसमें हिन्द महासागर से लगने वाले देश शामिल हैं। यह एक क्षेत्रीय फोरम है, इसमें सरकार, बिजनेस तथा शिक्षाविदों को सिंगल प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है।

बिम्सटेक

- बिम्सटेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के 7 देशों का समूह है, जो बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित हैं।
- इसकी स्थापना 6 जून, 1997 को बैंकॉक घोषणा के द्वारा की गयी थी।
- बिम्सटेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है।
- बिम्सटेक के सदस्य देश भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड हैं।
- इन सभी देशों की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 22% है।

उद्देश्य

- सदस्य देशों के बीच तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- बिम्सटेक देशों के बीच प्रमुख सहयोग क्षेत्र व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मतस्य उद्योग हैं।
- वर्ष 2008 में इसमें 8 और सेक्टर जोड़े गए थे, ये सेक्टर कृषि, जन स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद का सामना करना, पर्यावरण, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन तथा लोगों के बीच में संपर्क हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरूआत 1991 में वी.पी.सिंह की सरकार द्वारा की गई थी।
 2. बिमस्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के 7 देशों का समूह है।
 3. IORA की स्थापना का उद्देश्य हिन्द महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग तथा सतत् विकास को मजबूत करना था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1, 2, और 3

1. Consider the following statements-

1. Look East Policy was started in 1991 by the V.P. Singh government.
2. BIMSTEC is a group of seven countries in South Asia and South-East Asia
3. The objective of IORA establishment is to strengthen the regional cooperation and sustainable development.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) 1 and 2
- (b) 2 and 3
- (c) 1 and 3
- (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र आर्थिक और रणनीतिक रूप से वैश्विक महत्त्व के केन्द्र के रूप में उथर रहा है। भारत द्वारा इस क्षेत्र में अपनी महत्त्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने के संबंध में अभी तक किये गये प्रयासों का वर्णन कीजिए।

(250 शब्द)

Q. Indo-Pacific region is emerging as economical and political centre of global importance. Explain the efforts made by India to present itself in this region till now . (250 Words)

नोट : 17 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।